भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 4454**
**मंगलवार, 07 मई, 2013**
**देश में विद्युत उपकरण उद्योग की खराब स्थिति**

**4454. श्रीमती जया बच्चन:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में विद्युत उपकरण उद्योग की खराब स्थिति की ओर गया है;

(ख) क्या इस उद्योग का खराब निष्पादन विद्युत क्षेत्र के विकास के आड़े आ रहा है और उसे आयात पर निर्भर बना रहा है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री**
**(श्री प्रफुल पटेल)**

**(क):**इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग के पास विद्युत क्षेत्र की मांग को पूरा करने लायक पर्याप्त क्षमता स्थापित है। तथापि, हाल के वर्षों में देश के विद्युत क्षेत्र में मंदी के कारण सुस्त घरेलू मांग तथा इलेक्ट्रिकल उपकरण के आयात में तेजी की वजह से कई सारे उत्पादों के मामले में इस स्थापित क्षमता का फिलहाल कम उपयोग हो रहा है।

**(ख):**विद्युत क्षेत्र की वृद्धि में मंदी का कारण नई और मौजूदा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए ईंधन/कोयल संयोजनों में समस्याएं, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलें, पर्यावरणीय और अन्य अनापत्तियों की प्राप्ति में विलंब, विद्युत वितरण सेवा प्रदाताओं आदि की संकटपूर्ण वित्तीय स्थिति है। पंचवर्षीय अवधि 2006-07 से 2011-12 के दौरान डीजीसीआईएस आंकड़ों के अनुसार, भारत का इलेक्ट्रिकल उपकरणों का आयात रूपए के संदर्भ में 30% से अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा और वर्ष 2011-12 में 75,175 करोड़ रू. का हुआ। भारत में अब इलेक्ट्रिकल उपकरण के बाजार में 40% से अधिक का हिस्सा आयातित उपकरणों का है ।

**(ग) और (घ):** सरकार ने चीन समेत विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में घरेलू विद्युत उपकरण उद्योग द्वारा उठाई गई घाटे की स्थिति को कम करने के लिए 5% आयात शुल्क लगाने की शुरूआत की है।

उद्योग को विकसित करने और इसकी वृद्धि में गति लाने के लिए आईईईएमए की सहायता से और सभी प्रमुख हितधारकों के परामर्श से भारी उद्योग विभाग ने इलेक्ट्रिकल उपकरण मिशन प्लान (2012-22) तैयार किया है। इस मिशन प्लान में, सरकार और उद्योग दोनों के द्वारा रणनीतिक और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए पांच क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनमें उद्योग प्रतिस्पर्द्धात्मकता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, दक्षता विकास, निर्यात और अप्रकट मांग को प्रकट मांग में बदलना शामिल है ।

**(ड.)** शून्य । उपर्युक्त (ग) और (घ) को देखते हुए ।

*****